वर्ष : 03- अंक : 28 – जुलाई 2025

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

सहकारिता मंत्रालय के चार साल बेमिसाल

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार उदय
जुलाई 2025, अंक 28, वर्ष 03

संपादक मंडल
प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला
संपादक
रोहित कुमार
सह संपादक
अभिनव कुमार तिवारी
मानद सदस्य
एच. के. मिश्रा, लीयर लुइंगो
सदस्य
राहुल यादव, हितेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती मृणाल कारखिले, श्रीमती. सुरुचि कुमारी, राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें: प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017
इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop
IFFCO_PR
Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

सहकारिता मंत्रालय के चार साल बेमिसाल

सहकारिता आंदोलन के लिए छह जुलाई 2021 की तारीख सबसे अहम मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन का फैसला किया।

आवरण कथा

पेज 05 देखें

पेज 14 देखें

अर्थव्यवस्था के विकास केंद्र बनेंगे शहरी निकाय

भारत ने हमेशा प्रगति और सभी के कल्याण के लिए काम किया है और दुनिया में संकट के समय सहायता की पेशकश की है। वर्ष 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा और स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर हमें एक समृद्ध एवं मजबूत देश के रूप में वैश्विक मान्यता मिल जाएगी।

पेज 18 देखें

पीएम ने बिहार को दी बड़ी सौगात

बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर उसे देश के विकसित राज्यों के सामानांतर लाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।

पेज 20 देखें

आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग

पेज 25 देखें

औद्योगिक संभावनाओं वाला राज्य बन रहा उत्तर प्रदेश

पेज 22 देखें

भारत की विरासत की एक महान संरक्षिका थीं देवी अहिल्याबाई

पेज 27 देखें

आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपूर्व गति से काम कर रही सरकार

पेज 24 देखें

मौसम विज्ञान में विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचा भारत

पेज 29 देखें

कमजोर वर्गों को गरिमामय जीवन के साथ मिल रही आर्थिक मजबूती

चार साल बेमिसाल

छह जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सहकार से समृद्धि से के मूलमंत्र के साथ स्थापित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार साल पूरे हो गए हैं। यह कदम भारतीय सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास, समृद्धि कृषि व सामाजिक समरसता को नई दिशा देने की ओर मील का पत्थर साबित हुआ। बीते चार वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने सहकारिता को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाया है।

इन चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गईं, जिनमें प्रमुख हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियों का डिजिटलीकरण जिसके अंतर्गत देशभर की सभी पैक्स को एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया। इस पहल से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई। इसके साथ ही एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार किया गया, जो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है।

जैविक खेती, बीज उत्पादन तथा निर्यात हेतु राष्ट्रीय स्तर की तीन नयी बहुराज्यीय समितियों का गठन, नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण, डेयरी सहकारिता तथा सहकारी भंडार गृह निर्माण जैसी योजनाओं ने ग्रामीणजन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किये। भारत सरकार के सहयोग से इफको द्वारा विकसित नैनो यूरिया ने किसानों को सस्ते, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल उर्वरक की सुविधा दी, जिससे खेती की लागत घटाने में मदद मिल रही है।

सभी सहकारी संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे नीति-निर्माण और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं की सहकारी गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिला। इसके साथ ही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर भविष्य के सहकारी नेतृत्व को तैयार करने पर बल दिया जा रहा है।

निस्संदेह, सहकारिता मंत्रालय के इन चार वर्षों ने सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊर्जा, दृष्टि और दिशा प्रदान की है। यह दौर न केवल संस्थागत विकास का प्रतीक रहा है, बल्कि सामाजिक समरसता, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत का संकेत भी है। आने वाले वर्षों में यह सार्थक प्रयास 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

'सहकार उदय' पत्रिका के इस अंक में 'भारतीय सहकारिता के चार साल बेमिसाल' विषय पर सारगर्भित लेखों के साथ-साथ अन्य उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत की गई है। आशा है कि विगत अंकों की भांति 'सहकार उदय' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। ■

सादर धन्यवाद **जय सहकार**

बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

किसानों का सम्मान और उनकी समृद्धि मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रही है। कृषि प्रधान भारत में 2014 से पहले किसान हाशिये पर थे। मोदी सरकार ने डीबीटी, फसल बीमा योजना, सहकार से समृद्धि, केसीसी और ऐतिहासिक एसएसपी वृद्धि जैसे प्रयासों से किसानों की आय और सम्मान में वृद्धि सुनिश्चित की है। आज देश के किसान सशक्त हो रहे हैं और आत्मसम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किसानों को नियमित आर्थिक सहायता, महिलाओं को रसोई गैस, हर घर तक बिजली और शौचालय की सुविधा, और हर व्यक्ति को अपना पक्का घर, ऐसी सैकड़ों योजनाएं धरातल पर उतारी गईं, जिससे आम जनजीवन सरल हुआ। देश में सड़क, रेलवे, हवाई यात्रा और संचार में तेजी आई और डिजिटल सेवाओं के चलते आज देश के पिछड़े गांव भी 'स्मार्ट विलेज' बनते जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल,
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने 'सहकार से समृद्धि' का नारा दिया है और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सभी क्षेत्रों में सहकारिता को शशक्त करने के लिए कार्यरत हैं। सहकारिता के माध्यम से जल संरक्षण क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं और पानी बचाने एवं नल से जल योजना के तहत घरों में सप्लाई के लिए पैक्स बनाने पर काम हो रहा है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

इफको में हम 'सहकार से समृद्धि' का सपना और संकल्प साकार कर रहे हैं। देश की सहकारिता और देश के किसानों के लिये एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हुए आज विश्व पटल पर इफको को शीर्ष पायदान पर बरकरार रखा हुआ है। इफको अध्यक्ष श्री दीलीप संघाणी का सहकारी कौशल व नेतृत्व इफको को और मजबूती दे रहा है। हम इफको में कदम से कदम मिला कर चल रहे और आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इफको का सालाना प्रदर्शन इस बात को प्रमाणित करता है। जय सहकार।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहकारिता को भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में देखते हैं। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत 'सहकार से समृद्धि' इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पीएम मोदी का मानना है कि सहकारी संस्थाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं और किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम भी हैं।

सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

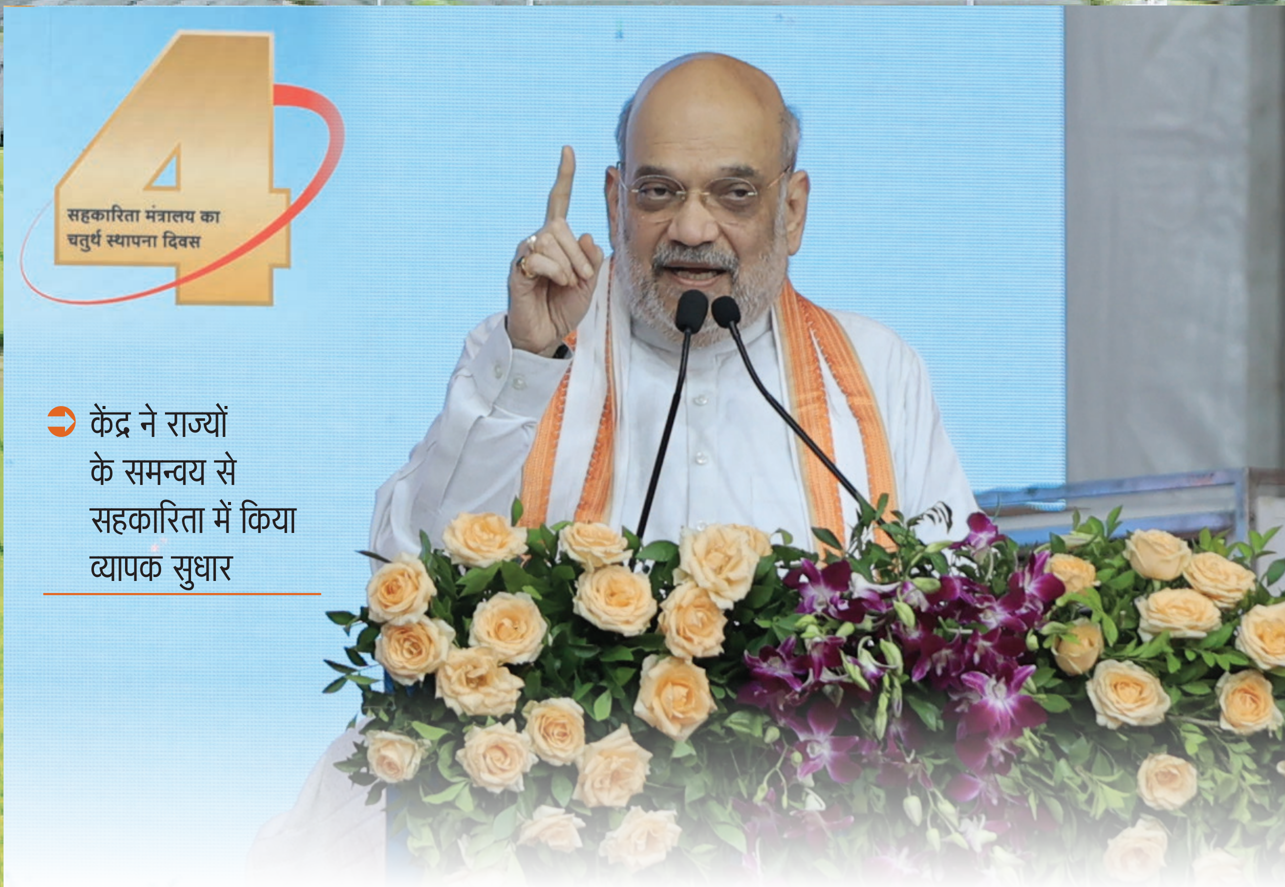

➲ केंद्र ने राज्यों के समन्वय से सहकारिता में किया व्यापक सुधार

सहकारिता मंत्रालय के चार साल बेमिसाल

सहकार उदय टीम

सहकारिता आंदोलन के लिए छह जुलाई 2021 की तारीख सबसे अहम मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन का फैसला किया। सहकारिता आंदोलन के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। सहकारिता क्षेत्र के लिए ये चार साल बेमिसाल साबित हुए हैं, जिसे सहकारिता क्षेत्र की दूसरी क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से देश में मंथर गति से चल रही सहकारिता को तेज रफ्तार मिली है। देश की सहकारिता में नई जान फूंकने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता व सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय रहे श्री अमित शाह को प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इन चार वर्षों के भीतर भारत के सहकारिता क्षेत्र में कुछ अहम पहल की गई है, जिससे सहकारिता की तस्वीर बदलने में मदद मिली है। कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार पर पूरा जोर दिया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिला है। सहकारिता क्षेत्र के हिसाब से देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के असंतुलन को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। दो लाख नए पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित कर सभी ग्राम पंचायतों को सहकारिता से जोड़ने का फैसला अहम साबित हुआ है।

राज्यों के समवन्य से सहकारिता को प्रोत्साहन

केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में श्री शाह ने सहकारिता की निचली इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं (अपेक्स) तक में सुधार का व्यापक फैसला लिया जिसे इन चार वर्षों के दौरान लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री शाह ने सहकारिता में सुधार के लिए संघीय ढांचे के अनुरुप राज्यों के सहयोग से इसे मूर्त देना शुरू किया। इसकी शुरूआत कानूनी सुधार से की गई जिसके लिए केंद्र के तैयार मॉडल कानून को केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सभी राज्यों ने स्वीकार कर अपने यहां सहर्ष लागू किया है। कानूनी सुधार से ठप पड़े पैक्स में कामकाज शुरू हो गया। उनके गठन की खामियों को दूर करने में मदद मिली है। पैक्स में महिलाओं, युवाओं और दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पैक्स में सदस्यता के लिए कोई भी आवेदन कर सकती है, किसी को सदस्य बनने से मना नहीं किया जा सकता है। राज्यों में सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक सुधार के साथ चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

कानूनी सुधार के प्रमुख तथ्यों की सूची

- प्रशासनिक सुधार
- चुनाव प्रक्रिया हुई पारदर्शी
- पैक्स में महिला, युवा और दलितों की सदस्यता अनिवार्य
- वित्तीय स्थिति हुई मजबूत

वित्तीय चुनौतियां दूर हुई

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता में सहकार की भावना को आगे बढ़ाते हुए कई फैसले किए जो सहकारी संस्थाओं के विकास में सहायक साबित हुई हैं। सहकारी संस्थाओं की वित्तीय चुनौतियों के मद्देनजर कई बड़े फैसले किए गए। इसके तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जैसी संस्था के ऋण वितरण का लक्ष्य कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। एनसीडीसी ने अपने गठन के बाद वर्ष 2014 तक जितना कुल ऋण वितरित किया था, उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई है। 31 मार्च 2025 तक एनसीडीसी का ऋण वितरण लक्ष्य 1.30 लाख करोड़ रुपए तय था, जिसमें से 95,175 करोड़ रुपए वितरित भी कर दिए गए हैं। जबक

पैक्स से अपेक्स तक हुए आनलाइन

पैक्स से लेकर अपेक्स तक की सहकारी संस्थाओं की पुरानी कार्य प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने निचली इकाई से लेकर शीर्ष सहकारी संस्था तक को आनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के कंप्युटरीकरण किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया है। इस सिस्टम के अपनाने से सहकारी क्षेत्र में धांधली की आशंका को सीमित कर दिया गया है। पैक्स कंप्युटरीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त वित्तीय मदद दी जा रही है। एक लाख से अधिक पैक्स में से पहले चरण में 67 हजार पैक्स को कंप्युटरीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमे से 47 हजार से अधिक पैक्स को कंप्युटरीकृत हो चुके हैं। कंप्युटरीकरण हो जाने के बाद पैक्स आनबोर्ड हो चुके हैं, जिससे वे सीधे केंद्रीय सर्वर से जुड़ गए हैं। इससे जहां कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है वहीं कामकाज में पारदर्शिता आई है।

1.05 लाख पैक्स पहले से हैं पंजीकृत

67 हजार पैक्स का किया जा रहा कंप्यूटरीकरण

47 हजार पैक्स कंप्युटरीकरण के बाद हुए ऑनबोर्ड

बदली पैक्स की तकदीर

मॉडल कानून लागू करने वाले राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना शुरू की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर एक दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर दो दर्जन से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से पैक्स को संबद्ध किया गया। इसी के चलते देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों पैक्स की कारोबारी दायरा बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। पेट्रोल पंप, गैस वितरण केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, गोदाम बनाने और रोजगार सृजन के अन्य कई योजनाओं का लाभ पैक्स को मिलने लगा है। यह सब इन्हीं चार वर्षों के भीतर संभव हो सका है।

(व्यावसायिक गतिविधियों एक सूची)

44,116

पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कर रहे हैं काम

36,689

पैक्स पीएम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में हुए अपग्रेड

22,330

पैक्स उचित मूल्य की राशन दुकानों के रूप में संचालित

2,758

पैक्स को पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मिली मंजूरी

19,349

पैक्स अनाज खरीद केंद्र के रूप में कर रहे काम

822

पैक्स की पानी समिति के रूप कार्य करने के लिए की गई पहचान

पैक्स से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां

- बीज, फर्टिलाइजर और कीटनाशक वितरण
- रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल डीलरशिप
- कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र
- खाद्यान्न खरीद, भंडारण (गोदाम व कोल्ड स्टोरेज) और कृषि उत्पादों की पैकेजिंग
- उचित मूल्य की राशन दुकानें
- मत्स्य पालन, डेयरी और पॉल्ट्री उद्योग
- फार्म मशीनरी कस्टम हायर सेंटर
- बागवानी उत्पादों की खेती
- मधुमक्खी, भेड़, बकरी व सूअर पालन
- रेशम उत्पादन
- सामुदायिक सेवा केंद्र, ब्रांडिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां
- बीमा सुविधा, बैंक मित्र व व्यावसायिक प्रतिनिधि
- हर घर नल से जल सेवा (जल जीवन मिशन)
- गोबर गैस
- बिजली बिल वितरण और कलेक्शन सेंटर
- लॉकर सुविधा

वर्ष 2024-25 में कुल ऋण वसूली 99.84 प्रतिशत रहा है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सहकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में देश की सहकारी संस्थाओं के समक्ष वित्तीय संकट की चुनौती समाप्त हो गई है। निचली इकाई पैक्स से लेकर अपेक्स तक धन की किल्लत नहीं हो रही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग और अन्य कारोबार में कई गुना की वृद्धि हुई हैऐ।

निष्क्रिय पैक्स की बहाली

सहकारिता क्षेत्र में निचले स्तर पर गठित 40 हजार से अधिक पैक्स निष्क्रिय हालत में है, जिन्हें सक्रिय करने के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया को सहज, सरल और आसाना बनाया जा रहा है। इससे लिक्विडेशन की प्रक्रिया को लागू करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय

सशक्त हुए सहकारी बैंक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से सहकारी बैंकों के व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनकी पहल से शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोल सकेंगे। सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे। उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संपर्क के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नोडल अधिकारी नियुक्त की मांग पूरी कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को डोर स्टेप सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुना से अधिक कर दिया है। ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट-आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी। सहकारी क्षेत्र के उद्यम सहकारी बैंकों से भी बिना किसी गारंटी के ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।

सहकारी बैंकों को आधुनिक ह्यआधार सक्षम भुगतान प्रणालीह्ल (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिल सकेगी। इससे अब किसानों को अपने घर पर ही अपनी उंगलियों के निशान से बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के राष्ट्रीय महासंघ को यूसीबी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) नामक एक छतरी संगठन (यूओ) के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन सहायता प्रदान करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पत्र 08 फरवरी, 2024 के माध्यम से अम्ब्रेला संगठन को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया है, जिससे संगठन को सर्वसम्मति नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है।

सहकारी डेटाबेस के अनुसार, देश में इस समय कुल 8,43,099 सहकारी समितियां हैं। इनमें से प्राथमिक समितियां 8,39,244 हैं जिनमें सक्रिय समितियों की संख्या 6,44,608 हैं। 1,48,329 सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं। इसी तरह कुल 46,307 समितियां लिक्विडेशन में हैं।

डेयरी और मत्स्य कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन

ग्रामीण भारत के कृषि क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका बहुत अधिक है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश के ज्यादातर गांव सहकारिता से संबद्ध हैं। लेकिन डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में सहकारिता का प्रसार तुलनात्मक रूप से कम है। सहकारिता ने कमजोर वर्ग के उत्थान के

सहकारी चीनी उद्योग को मिला बूस्टर डोज

बीते चार वर्षों में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों में शुगर इंडस्ट्री को प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। वित्तीय घाटे, अतार्किक कर प्रणाली और कानूनी चुनौतियों से जूझ रही सहकारी चीनी मिलों के लिए नया मंत्रालय और पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह वरदान साबित हुए। उनकी समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें दूर करने का प्रयास पहले चरण में ही कर दिया गया। केंद्रीय आयकर और जीएसटी जैसी मुश्किलें उन्हें मुश्किलों से उबरने नहीं दे रही थी। नये मंत्रालय के गठन के बाद आये केंद्रीय आम बजट में कई ऐसे प्रावधान लाए गए, जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि सहकारी चीनी मिलों के ऊपर 10 हजार करोड़ रुपए का पुराना बकाया भी माफ कर दिया गया। उनके वित्तीय लेनदेन की प्रणाली को आसान बना दिया गया। नगदी भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई। चीनी उद्योग से जुड़े एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे सहकारी मिलों को घाटे से उबरने में मदद मिली है। पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया।

लिए मत्स्य व डेयरी क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र पहले से ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की तटीय सीमा 7500 किमी है जिसमें मत्स्य पालन और मत्स्य कारोबार की अपार संभावनाएं है। इसी तरह देश में नदियां, झील और गांव गांव में पोखर तालाबों की संख्या बहुत अधिक है। इसके मद्देनजर आंतरिक मत्स्य पालन की भी संभावनाएं बहुत है। इस क्षेत्र में संलग्न मानव संसाधन गरीब और पिछले हुए समाज के लोग हैं, जिनके लिए सहकारिता एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इन्हीं सबको देखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने मत्स्य सहकारी समितियों के गठन पर ज्यादा जोर दिया है, ताकि उन्हें रियायती दर पर वित्तीय व तकनीकी मदद मुहैया कराई जा सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से मदद पहुंचाने की पहल की है। डेयरी सहकारी क्षेत्र की कई संस्थाओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय है जिससे लाखों पशुपालकों के जीवन में बदलाव आया है। अमूल जैसी डेयरी सहकारी संस्था वैश्विक स्तर पर अपने झंडे गाड़ रही है।

कोऑपरेटिव को कॉरपोरेट की तर्ज पर टैक्स में छूट

सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं पर अतार्किक रूप से लगाए जा रहे इनकम टैक्स से कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहती थी, जिसमें जरूरत के मुताबिक आमूल संशोधन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र और कंपनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से एक करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए आयकर

पर अधिभार को कंपनियों के समान सात प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 12 प्रतिशत था। सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है।

31 मार्च, 2024 तक मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों पर अधिभार सहित 30 प्रतिशत को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समानता होगी। सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती के बिना नकद निकासी की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी है। सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ

एक दिन में किए गए दो लाख से कम के नकद लेनदेन को अलग से माना जाएगा। उन पर आयकर जुमार्ना नहीं लगाया जाएगा। इससे राज्य और जिला दुग्ध संघ एक दिन में अब दो लाख रुपए से कम का भुगतान नकद में अपने वितरकों से प्राप्त कर सकेंगे और बैंक अवकाश के दौरान सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नकद में भुगतान कर सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की भागीदारी

किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर सहकारिता मंत्रालय ने विशेष बल दिया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है।

देश के 11 राज्यों में पीएम अन्न भंडारण योजना की उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि संबंधी ढांचागत निर्माण के तहत 500 पैक्स में इन गोदामों की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश में अनाज भंडारण की क्षमता में सात करोड़ टन तक की वृद्धि हो जाएगी। ■

तीन प्रमुख सहकारी सोसाइटियां गठित

देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय ने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी समितियों को गठन कर दिया है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स समिति लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड प्रमुख हैं। इन तीनों राष्ट्रीय समितियों से देश में किसानों की जहां आमदनी बढ़ेगी वहीं सहकारिता क्षेत्र नई ऊचाइयां छुएगा। कृषि उपज की सरकारी खरीद में सहकारी एजेंसियों को और सक्रिय कर दिया गया है। दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की मंशा के अनुरूप दो प्रमुख सहकारी एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ सरकारी खरीद में और सक्रिय हो गई हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित व लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों को उचित एवं लाभकारी मूल्य अथवा राज्य परामर्शित मूल्य तक किसानों को उच्च गन्ना मूल्य के भुगतान पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अब अपने सदस्यों को गन्ने का मूल्य दे सकेंगी तथा उन्हें इस व्यय पर आयकर में छूट मिलेगी। सहकारिता मंत्रालय ने ह्यसहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके तहत भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए करेगा। इसका उपयोग वे एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या तीनों उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे। एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अन्तर्गत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल खरीद के लिए निजी कंपनियों के बराबर रखा जाएगा। सरकार ने गुड़ पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की भारी मांग के मद्देनजर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। सहकारिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। गुजरात के आणंद में स्थापित होने वाले सहकारी विश्वविद्यालय से देशभर के सहकारी महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा।

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

यूपी पुलिस के हजारों कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरण के मौके पर बोले श्री अमित शाह

पुलिसबलों के आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस

- उत्तर प्रदेश में न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, न जातिवाद, केवल योग्यता के आधार पर 60,244 युवाओं की भर्ती होना शासन की बड़ी उपलब्धि
- सेवा, सुरक्षा और संवेदनशीलता के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे नवनियुक्त पुलिसकर्मी

सहकार उदय टीम

हमारा भारत वर्ष 2047 में दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सूबे की सरकार ने शिक्षा, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से लेकर हर गांव और घर तक बिजली एवं नल से जल पहुंचाने और सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक सफलतापूर्वक पहुंचाकर बड़ा परिवर्तन किया है। इन विकासमूलक उपलब्धियों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के मौके पर साझा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुल 48 लाख आवेदकों में से इन सुयोग्य युवाओं का चयन किसी प्रकार की खर्ची, पर्ची, सिफारिश, जातिगत आधार या रिश्वत जैसे भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। इन चयनित होनहारों में 12 हजार से अधिक बालिकाएं भी हैं, जिनके हौसले और चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए जिस आरक्षण की व्यवस्था की है, उसका उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत अनुकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये युवा अमृतकाल के ऐसे समय में प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं, जब राज्य नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं और यूपी को विकसित के साथ-साथ सुरक्षित बनाने का ज़िम्मा अब इन युवाओं का है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देशभर में वर्ष 2014 से ही पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई, लेकिन यूपी में यह शुरुआत तीन साल देरी से हो सकी। वर्ष 2014 से 2017 तक भारत सरकार की सुधार प्रक्रियाओं का कोई असर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी, जिससे यहां की कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। लेकिन, श्री योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई और सूबे की पुलिस नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। श्री शाह ने कहा कि यूपी का पुलिस बल पूरे देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, जहां वर्तमान समय में कैमरे, कंट्रोल रूम, कमांड सेंटर, पीसीआर-1 और 150

से अधिक ऑन-व्हील फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) यूनिट्स लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं और सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता के मंत्र के साथ इन होनहार युवाओं को इसे आगे बढ़ना होगा। नियुक्ति पत्र लेने आए युवा सिपाहियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि गुंडों और माफिया के मन में पुलिस का डर होना चाहिए और गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को पुलिसकर्मियों के रूप में मसीहा दिखाई देना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि किसी जमाने में दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से दंगामुक्त हो चुका है। प्रदेश में न्याय का शासन है और अब गुंडों का फरमान नहीं चलता और न ही अपराधियों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को युवा सिपाहियों को आगे बढ़ाना है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का हो रहा व्यापक असर

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के सेवाकाल में सरकार ने भारत को आगे बढ़ाया है और अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला किया है। इस दौरान देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस सिलिंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, पांच किलो मुफ्त अनाज, और पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया है और हर किसान को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के सभी युवाओं के लिए रोजगार और विकास के अनेक अवसर पैदा किए हैं। नई शिक्षा नीति और कंप्युटर आदि की तकनीकी शिक्षा से युवा सामर्थ्यवान बन रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने की आकांक्षा से सरकार ने सुदूरवर्ती गांवों तक सड़कों का व्यापक विस्तार किया है और उन्हें शहरों को जोड़ा है और 150 से अधिक एयरपोर्ट का निर्माण किया है। इन वर्षों में देश में 143 से अधिक शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है।

तय समय सीमा में ही मिलेगा न्याय

श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर अमल से अगले पांच वर्षों में ऐसी स्थिति आएगी कि देश में किसी भी एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय मिलेगा। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस), नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस), अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) और फॉरेंसिक साइंस की सभी सुविधाओं के साथ न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था तकनीक के आधार पर की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी और अब भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है। श्री शाह ने विश्वास पूर्वक कहा कि वर्ष 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष फोकस

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश सुरक्षित हुआ है। जहां पहले देश के 11 राज्यों में नक्सलवाद फैला था, वह अब सिमटकर सिर्फ तीन ज़िलों में बचा है। उन्होंने दोहराया कि 31 मार्च, 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जहां देश में आए दिन आतंकी हमले होते थे, वहीं मोदी सरकार में पाकिस्तान ने उरी, पुलवामा और पहलगाम में तीन बार हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया, जबकि पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया में यह संदेश भेजा कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं है और जो भी ऐसा हिमाकत करेगा, उसे सख्त से सख़्त दंड दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि हमारी सेनाओं की सटीक मारक क्षमता ने आतंकवादियों के उन ठिकानों को जमींदोज कर किया, जहां से आतंकवादी गरजकर इंटरव्यू देते थे। यह सशक्त भारत के एक नए युग की शुरुआत है। ■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

गुजरात के शहरी विकास संबंधी आयोजन में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

अर्थव्यवस्था के विकास केंद्र बनेंगे शहरी निकाय

- आजादी के 100 साल का उत्सव भारत इस तरह मनाएगा कि पूरी दुनिया 'विकसित भारत' की जय-जयकार करेगी
- शहरों को आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और नगर निकायों को उनके परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए
- देश में लगभग दो लाख स्टार्ट-अप हैं, जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में है

सहकार उदय टीम

भारत ने हमेशा प्रगति और सभी के कल्याण के लिए काम किया है और दुनिया में संकट के समय सहायता की पेशकश की है। वर्ष 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा और स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर हमें एक समृद्ध एवं मजबूत देश के रूप में वैश्विक मान्यता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन विचारों को गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास पर केंद्रित एक समारोह में साझा किया। राज्य के शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों के लिए सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर प्रशासन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से राज्य के शहरी परिदृश्य को बदलना था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, ''शहरों को आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और नगर निकायों को उनके परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए।'' उन्होंने शहरी विकास के प्रति गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने अनुभवों का उपयोग अगली पीढ़ी के लिए अनुकूल भविष्य-केंद्रित शहरी विकास का रोडमैप बनाने में किया है।

विकास के लक्ष्य को पाने में शहरों की बड़ी भूमिका

देश भर के नगर निगम और महानगरीय अधिकारियों से अपने-अपने शहरों के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करने का

आर्थिक विकास को गति देने में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

गुजरात के हुए बदलावों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने आर्थिक विकास को गति देने में पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कच्छ जो कभी अपने रेगिस्तानी परिदृश्य के कारण अनदेखा किया जाता था, अब एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जैसी बड़े पैमाने की पहल ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। उन्होंने वडनगर जैसे स्थलों के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए इसके संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विरासत केंद्र बताया। श्री मोदी ने भारत की समुद्री विरासत का जिक्र किया और कहा कि लोथल अब दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालयों में से एक है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी अब वित्तीय केंद्रों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। साबरमती रिवरफ्रंट दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई बड़े पैमाने की सफल परियोजनाओं का जिक्र कर श्री मोदी ने कहा कि ये भारत की परिवर्तनकारी पहलों को क्रियान्वित करने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं।

आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करें और एक वर्ष के भीतर इसे बढ़ाने के तरीकों की रणनीति पर काम करें। आर्थिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते तलाशने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह शहरी निकायों को कृषि आधारित उद्योगों के समर्थन और स्थानीय बाजारों में मूल्यवर्धित पहलों को लागू करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महानगरीय क्षेत्रों की जगह टियर-2 और टियर-3 शहरों में लगभग दो लाख स्टार्टअप का उदय होना देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव को बयां करता है। इनमें से कई उपक्रमों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि आर्थिक और उद्यमशीलता की क्रांति की एक नई लहर का संकेत है। श्री मोदी ने कहा कि शहरी आर्थिक परिवर्तन पर भारत का ध्यान देश की चौथी से तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में तेजी लाएगा।

वैश्विक शांति और समृद्धि का आकांक्षी है भारत

श्री मोदी ने प्रगति और वैश्विक कल्याण में योगदान के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता तथा शांति और समृद्धि की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय के साथ भारत अपने नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके सेवाकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान से बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रगति के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व औपनिवेशिक शासक यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के महत्व पर बल देते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी में स्थानांतरित होने की भारत की महत्वाकांक्षा को दुहराया। श्री मोदी ने नागरिकों से अपने दैनिक उपभोग का आकलन करने, विदेशी उत्पादों की पहचान करने और उन्हें स्थानीय रूप से बने विकल्पों के साथ बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अतीत में विदेशी वस्तुओं की मांग थी, लेकिन आज भारत में घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की क्षमता है। राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत में निर्मित उत्पादों पर गर्व करने और अपने देश की प्रगति का जश्न मनाने का भी आह्वान किया और कहा कि हमें अपने ब्रांड 'मेड इन इंडिया' पर गर्व होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसकी वैश्विक स्थिति सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए।

देश में एक बड़ा बदलाव लाने की अपार क्षमता

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर पिछली पीढ़ियां 20-35 वर्षों में औपनिवेशिक शासकों को बाहर निकाल सकती हैं, तो निश्चय ही आज भारत के 140 करोड़ नागरिक अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं के बलिदानों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उस समय की 25-30 करोड़ आबादी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होती, तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। वर्ष 2035 को गुजरात की 75वीं वर्षगांठ के लिए योजना बनाने पर जोर देकर श्री मोदी ने कहा कि उद्योग, कृषि, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षाओं का जिक्र किया और कहा कि हमारा देश वैश्विक नेतृत्व के लिए तत्पर है।

प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि शहरी विकास के लिए सरकार की दृढ़ संकल्पित है। देश में विकास के मार्ग में नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें लगभग 40 विकासात्मक मापदंडों के आधार पर लगभग 100 जिलों की पहचान की गई थी और एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ समर्पित अधिकारियों को तैनात किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल की सफलता अब विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन गई है। ■

आपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से गोलीबारी पर बोले श्री अमित शाह

सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को तहस-नहस करके दुनिया को अपनी 'आतंक पर जीरो टालरेंस' की नीति को प्रमाणित कर दिया। लेकिन, उसके बाद भी पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी की गई, जिससे बहुत से मकान क्षतिग्रस्त हुए। इन पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के लिए मोदी सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा राशि सुनिश्चित की और विशेष मामले के रूप में, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए दो लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए एक लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा की गई। सरकार के इस निर्णय का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2060 घरों के लिए 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया और कहा कि मोदी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से मुआवजा दिया जायेगा।

- क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रत्येक घर के लिए दो लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक-एक लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा राशि
- श्री शाह ने 2060 घरों के लिए 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया

भारत सरकार अपने सीमावर्ती नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करने और पीड़ित परिवारों के जीवन को फिर से खुशहाल बनाने में उनकी मदद करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर जाकर प्रभावित परिवारों के लिए निरंतर राहत सुनिश्चित करने और उनके घरों को फिर से आबाद करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस दिशा में सक्रिय कदम बढ़ाते हुए श्री शाह ने भी पुंछ का दौरा किया और सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा था। उनके निर्देशन पर सीमा पार गोलाबारी के कारण हुई क्षति के लिए मानकों के अनुसार तत्काल ही लोगों को मुआवजा दिया गया।

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पार से गोलाबारी की कई घटनाएं सामने आईं थीं, जिनसे सैकड़ों परिवार पीड़ित हुए। गोलीबारी से रिहायशी इलाकों, स्कूलों, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और व्यावसायिक संपत्तियों सहित धार्मिक संरचनाओं की क्षति हुई, जिनके निराकरण के लिए प्रशासन ने प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए और संभावित घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस पहल की। इस कार्रवाई में सीमावर्ती जिलों से कुल 3.25 लाख नागरिकों को निकाला गया और इनमें से लगभग 15,000 लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली आदि सुविधाओं से युक्त करीब 400 आश्रय स्थलों एवं आवास केंद्रों में सुरक्षित रखा गया।

इस दौरान सभी सीमावर्ती जिलों में रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए करीब 400 एम्बुलेंस लगाए गए, जिनमें से 62 एम्बुलेंस अकेले पुंछ जिले में तैनात किए गए। नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, पशुधन और आवश्यक आपूर्ति आदि से संबंधित सेवाओं के लिए 2,818 नागरिक रक्षा स्वयं सेवकों को भी मौके पर नियुक्त किया गया। ■

विकसित कृषि संकल्प अभियान में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कृषि बनेगी विकसित भारत का मुख्य आधार

सहकार उदय टीम

विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कृषि के विकास को समर्थन देने और इसे मजबूत बनाने का एक अनूठा प्रयास है, जिसके तहत वैज्ञानिकों का दल देशभर में किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी देगा और किसानों की मदद के लिए सभी डेटा उपलब्ध कराएगा। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान देशवासियों से साझा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के 2,000 दल देश के 700 से अधिक जिलों का दौरा करेंगे और सुदूर के गांवों तक के लाखों किसानों से संपर्क कर उन्हें खेती की विभिन्न उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। जब वैज्ञानिकों के दल प्रयोगशाला से खेतों तक जाएंगे और किसानों के बीच व्यापक डेटा पहुंचाने के साथ उन्हें कृषि से जुड़े उन्नत ज्ञान से अवगत कराकर किसानों की सहायता करेंगे।

देश में समय के अनुकूल आधुनिक तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए राज्यों और किसानों के सहयोग से कृषि प्रणालियों में आधुनिक सुधार लाना जरूरी है। उन्होंने कृषि के परंपरागत रूप से राज्य का विषय होने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के सभी राज्यों के किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने और नई पहल करने पर सरकार का फोकस है। देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन और अनाज के भंडारों के भरे होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने किसानों को सचेत किया कि बाजार का स्वरूप और उपभोक्ता प्राथमिकताएं लगातार बदल रही हैं। पिछले कुछ दशकों में देश के कृषि वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण रिसर्च और प्रगति का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों के नवीन खोजों ने खेती के परिणामों पर सकारात्मक असर डाला है। उन्होंने देश के उन प्रगतिशील किसानों की तारीफ की जिन्होंने नई तकनीकों को खेती में अपनाकर सफलता हासिल की है और प्रभावशाली पैदावार के जरिए समृद्धि की ओर बढ़े हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और सफल कृषि पद्धतियों को व्यापक कृषक समुदाय तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अब इन पहलों को नई ऊर्जा के साथ तेज करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, ''विकसित कृषि संकल्प अभियान इस ज्ञान के अंतर को पाटने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे किसानों को अत्याधुनिक कृषि से जुड़ी जानकारियों से लाभ मिल सके।''

➲ देश के 700 से अधिक जिलों का करेंगी दौरा करेंगी वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की 2,000 हजार टीमें

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश की जरूरतों के हिसाब से फसल उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देकर कहा, ''भारत को न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरना चाहिए।'' जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, न्यूनतम जल उपयोग के साथ अनाज उत्पादन को बढ़ाना, हानिकारक रसायनों से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेतों तक ले जाना आवश्यक है। पिछले 10-11 वर्षों में सरकार ने इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए हैं। श्री मोदी ने कहा, ''विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत के किसानों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा, कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा।'' ■

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

पीएम ने बिहार को दी बड़ी सौगात

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया
- पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल बना आधुनिक, बिहार के मखाना को मिला जीआई टैग जिससे मखाना किसान हो रहे लाभान्वित

सहकार उदय टीम

बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर उसे देश के विकसित राज्यों के सामानांतर लाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें सड़क, एयरपोर्ट, बिजली और रेलवे की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, फेज-2 की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फेज-2 के तहत 800 मेगावाट की बिजली क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किफायती बिजली उपलब्ध होगी। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एनएच-119ए के पटना-आरा-सासाराम खंड को चार लेन का बनाने, वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग (एनएच-319बी) और रामनगर-कच्ची दरगाह खंड (एनएच-119डी) को छह लेन का बनाने और बक्सर-भरौली के बीच गंगा पर नए पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

ये परियोजनाएं राज्य में निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के साथ-साथ व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देंगी। उन्होंने एनएच-22 के पटना-गया-डोभी खंड पर बने फोर लेन रोड का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत लगभग 5,520 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एनएच-27 पर गोपालगंज शहर में बने फोर लेन एलिवेटेड हाईवे और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन किया। देशभर में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की।

बढ़ रही रेल, सड़क और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। टूटी हुई सड़कें, खस्ताहाल रेलवे और सीमित उड़ान कनेक्टिविटी के दिन अब अतीत की बात हो गए हैं। बिहार में पहले केवल पटना हवाई अड्डा था, लेकिन आज दरभंगा हवाई अड्डा भी कार्यशील है जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है। बिहटा में भी 1,400 करोड़ रुपए के निवेश से नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने बिहार

दौरे के दौरान पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। नया टर्मिनल सालाना एक करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है।

राज्य में चार लेन और छह लेन की सड़कों के व्यापक विकास पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पटना से बक्सर, गया से डोभी और पटना से बोधगया को जोड़ने वाले राजमार्गों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भी उल्लेख किया, जहां काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने गंगा, सोन, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियों पर नए पुलों के निर्माण की जानकारी दी और बिहार के लिए नए अवसरों और संभावनाओं को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार सृजित कर रही हैं। ये पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा दे रही हैं।

बिहार के रेलवे बुनियादी ढांचे में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने राज्य में विश्वस्तरीय वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे लाइनों के दोहरीकरण एवं तिहरेकरण की चल रही प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छपरा, मुजफ्फरपुर और कटिहार जैसे क्षेत्रों में रेलवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोन नगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है जिससे ट्रेनों की आवाजाही में काफी सुधार होगा। अब सासाराम में 100 से अधिक ट्रेनें रुकती हैं जो इस क्षेत्र की बढ़ती कनेक्टिविटी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

बिजली परियोजनाओं पर बिहार का फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में बिजली उत्पादन पर काफी ध्यान केंद्रित किया है। बिजली के बिना विकास अधूरा है। औद्योगिक प्रगति और जीवन की सुगमता विश्वसनीय बिजली आपूर्ति पर निर्भर करती है। पिछले एक दशक पहले की तुलना में बिहार में बिजली की खपत चार गुना बढ़ गई है। नबीनगर में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से एनटीपीसी की एक प्रमुख बिजली परियोजना निमार्णाधीन है। यह परियोजना बिहार को 1,500 मेगावाट बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने बक्सर और पीरपैंती में नए थर्मल विद्युत संयंत्रों की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला। भविष्य पर ध्यान देने, विशेष रूप से बिहार को हरित ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने राज्य की अक्षय ऊर्जा पहल के हिस्से के रूप में कजरा में एक सौर पार्क के निर्माण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा की कि पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आय उत्पन्न करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि अक्षय कृषि फीडर खेतों को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं जिससे कृषि उत्पादकता में और सुधार हो रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लोगों के जीवन में सुधार हुआ है और महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। ■

75 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा गांवों, गरीबों, किसानों और छोटे उद्योगों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। इससे वे बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ सकते हैं। बेहतर परिवहन सुविधाएं किसानों को अपनी उपज को अधिक दूरी तक बेचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलती है। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में 75 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है और बिहार के मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इससे मखाना किसानों को अत्यंत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की घोषणा भी की गई है।

आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग

- नया भारत 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की शक्ति से विकसित और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है
- जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं मोदी सरकार के ऐतिहासिक वर्ष

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। इन वर्षों में सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तुष्टीकरण की नीति की जगह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की कार्य संस्कृति बनाई और विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हितों और उनके समग्र विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नए भारत की उपलब्धियों पर जोर देते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री शाह ने कहा कि जनसेवा के इन वर्षों में मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग और नीयत लोकसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। भारत ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। जनसेवा के इन

- पीएम उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को दी धुआं मुक्त जिंदगी
- मुद्रा योजना से महिलाओं को मिला नया आत्मविश्वास
- देश के अन्नदाताओं का स्वाभिमान बनी पीएम किसान योजना
- तकनीक के पंखों पर सवार भारत का युवा कर रहा है नवोदित आविष्कार
- पीएम-किसान सम्मान योजना से अब तक 3.68 लाख करोड़ रुपए की राशि 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित

राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में स्थापित किया मील का पत्थर

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। सरकार की विकासमूलक ठोस रणनीति और नक्सलमुक्त भारत अभियान के परिणामस्वरूप देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। देश के अशांत रहे क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना हुई है। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकियों के घर में घुस कर देता है। यह भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।

स्वावलंबी युवा शक्ति ही विकसित भारत की नींव

मोदी सरकार बीते 11 वर्षों से देश की युवा शक्ति को शिक्षा से लेकर रोजगार और खेल से लेकर नवाचार तक नई पहचान दे रही है। मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, स्किल इंडिया, स्वनिधि, खेलो इंडिया जैसी पहलों से देश में युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मगौरव से युक्त देश के युवा भारत को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वर्षों के दौरान 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' से देश के विकास की स्पीड और स्केल दोनों को बदला गया है। श्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की शक्ति से विकसित और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में जब श्री मोदी ने देशसेवा की बागडोर संभाली थी, तब भारत में 'पॉलिसी पैरालिसिस' था। उस समय देश में नीतियों और नेतृत्व का अभाव था, जिससे अर्थव्यवस्था जर्जर और शासन व्यवस्था दिशाहीन हो गई थी और सरकार में घोटाले चरम पर थे। पूर्ववर्ती सरकार की तुष्टीकरण की नीति की जगह मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की कार्य संस्कृति बनाई। सरकार ने देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर विकसित और 'हर क्षेत्र में नंबर वन भारत' बनाने की यह यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी।

युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय पहल

श्री शाह ने कहा कि युवा शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार बहुस्तरीय पहल कर रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से अबतक युवाओं को 10 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.42 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। देश में हर महीने एक यूनिकार्न तैयार हो रहा है और इस दौरान 1.76 लाख से अधिक स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया है। मोदी सरकार ने देश में 570 विश्वविद्यालयों, सात नए आईआईटी, आठ नए आईआईएम और 15 एम्स और 16 ट्रिपल आईटी एवं 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है। खेलो इंडिया के तहत 27,500 से अधिक एथलीटों और 45,500 से अधिक प्रतिभागियों को सहायता प्रदान की है। सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, जो युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदान करने का माध्यम बनेगी।

नारी शक्ति को हर क्षेत्र में किया सशक्त

सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा, समृद्धि और सशक्तीरण के लिए अनेक पहल किया है। महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 73 प्रतिशत मकानों को महिलाओं के नाम आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं ही हैं। स्टैंडअप इंडिया योजना के लाभार्थियों में भी 74 प्रतिशत उद्यमी महिलाएं ही हैं। इस दौरान 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है।

मोदी सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम के तहत संसद के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को कानून का स्वरूप प्रदान किया है। कामकाजी महिलाओं को वेतनयुक्त मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करके महिलाओं के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को सरकार ने 18,593 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। मोदी सरकार ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। सरकार की पहल से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ खाते खोले गए हैं।

श्री शाह ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और वर्ष 2013-24 की तुलना में कृषि बजट में वृद्धि करते हुए 2025-26 में इसे पांच गुना कर दिया है। देशभर में 10 हजार से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

भोपाल में महिला सशक्तीरण महासम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

भारत की विरासत की एक महान संरक्षिका थीं देवी अहिल्याबाई

सहकार उदय टीम

- राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक हैं माता अहिल्याबाई
- नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा प्रोत्साहन, बढ़ रही उनकी आय

लोकमाता देवी अहिल्याबाई दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। ढाई सौ से तीन सौ साल पहले, जब देश उत्पीड़न की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन्होंने ऐसे असाधारण और बड़े कार्य किए, जिन्हें आज भी पीढ़ियां याद करती हैं। लोकमाता ने राज्य की समृद्धि को एक नई दिशा प्रदान की और स्वयं को सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तीरण महासम्मेलन में व्यक्त किया।

श्री मोदी ने कहा, ''लोकमाता अहिल्याबाई भारत की विरासत की एक महान संरक्षक थीं।'' ऐसे समय में जब देश की संस्कृति, मंदिर और तीर्थ स्थलों पर हमला हो रहा था, उन्होंने उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित देश भर में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार में उनके योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कभी भी ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा के बीच अंतर नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि माता अहिल्याबाई ने एक अनुकरणीय शासन मॉडल लागू किया, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल किए और कृषि व वन उपज पर आधारित कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लोकमाता ने छोटी नहरें बनवाईं और कई तालाबों का निर्माण कराकर जल

संरक्षण के प्रयास किए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया।

श्री मोदी ने आदिवासी समुदायों और खानाबदोश समूहों के लिए उनके दूरदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने इन समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए अप्रयुक्त भूमि पर कृषि में सहयोग दिया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियों के लिए नए उद्योग स्थापित करके वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई के योगदान को याद किया, जिससे देश के बुनकरों को बहुत लाभ हुआ। इसके लिए देवी अहिल्याबाई ने गुजरात के जूनागढ़ से कुछ साड़ी बुनने वाले परिवारों को आमंत्रित कर यह काम शुरू किया था। श्री मोदी ने कहा, 'देवी अहिल्याबाई होल्कर को हमेशा लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करने जैसे उनके महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनके समय में चर्चा करना भी मुश्किल था।' उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक चुनौतियों के बावजूद देवी अहिल्याबाई ने इन प्रगतिशील सुधारों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने मालवा सेना में एक विशेष महिला यूनिट भी बनाई और गांवों में महिला सुरक्षा समूह स्थापित किए जिससे सुरक्षा और सशक्तीरण सुनिश्चित हुआ। श्री मोदी ने कहा, ''माता अहिल्याबाई राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के अमूल्य योगदान का प्रतीक हैं''।

'नागरिक देवो भव' के सिद्धांत पर कार्य कर रही सरकार

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई होल्कर के उस प्रेरक कथन को याद किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह लोगों का ऋण है, जिसे चुकाना होगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार उन्हीं मूल्यों के अनुरूप 'नागरिक देवो भव' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को राष्ट्र की प्रगति के मूल में रखा जा रहा है। सरकार की हर बड़ी पहल माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। वंचितों के लिए चार करोड़ घर बनाए गए हैं जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। देश में यह पहली बार है कि महिलाओं का नाम संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है। यह एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है जहां देश भर में करोड़ों महिलाएं पहली बार घर की मालकिन बनी हैं।

सरकार हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है जिससे महिलाओं की कठिनाइयों को कम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पहले करोड़ों महिलाएं बिजली, एलपीजी गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थीं। सरकार ने इन महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रदान करके ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की माताओं और बहनों के जीवन में काफी सुधार किया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस

प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार के निरंतर प्रयासों का जिक्र कर कहा कि वर्ष 2014 से पहले 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था। सरकार ने उनके लिए जन धन खाते खोलने की सुविधा प्रदान की, जिनमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं मुद्रा योजना द्वारा समर्थित काम और स्वरोजगार में तेजी से शामिल हो रही हैं। यह योजना बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''मुद्रा की 75 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।''

देश भर में 10 करोड़ महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। ये समूह सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता से आय के नए स्रोत बना रहे हैं। श्री मोदी ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैंक सखियां गांवों में लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ रही हैं और बीमा सखियां देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

नीति निर्माण में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी

नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है। वर्तमान में 75 महिलाएं संसद सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस भागीदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को मजबूती दी गई है।■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

नई दिल्ली में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में बोले श्री अमित शाह

मौसम विज्ञान में विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचा भारत

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का आपदा प्रबंधन 'शून्य दुर्घटना दृष्टिकोण' के साथ आगे बढ़ रहा है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समुचित तैयारियां सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रतिवर्ष की भांति मानसून से पहले ही देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की पड़ताल के लिए नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी जानकारी ली। इस दौरान श्री शाह ने बाढ़ प्रबंधन के लिए सभी एजेंसियों द्वारा अपनाई गई नई तकनीकों और उनके नेटवर्क के विस्तार का जिक्र करते हुए बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत पीछे था, लेकिन श्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों के बराबर की स्थिति में हैं और अब हमें पहले स्थान पर पहुंचना है।

श्री शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि वह जमीनी स्तर तक पूर्व चेतावनी अलर्ट का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के साथ समन्वय स्थापित करे। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बाढ़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए द्वारा जारी सलाहों के समय पर क्रियान्वयन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीएमए और एनडीआरएफ के राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से बाढ़ प्रबंधन का कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होगा। श्री शाह ने बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सराहना करते हुए पूर्वानुमानों की सटीकता के स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बाढ़ निगरानी केंद्रों को देश की आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का आह्वान किया और ग्लेशियल झीलों की बारीकी से निगरानी करने पर जोर दिया, जिससे किसी भी तरह के विस्फोट की स्थिति में समय पर कार्रवाई की जा सके। श्री शाह के निर्देशन पर ही देश में बाढ़ पूर्वानुमानों की जानकारी अब तीन दिन की जगह सात दिनों पहले ही जारी की जा रही है। गर्मी के मौसम में हीटवेव पूर्वानुमानों के लिए भी बेहतर पैरामीटर अपनाया गया है।

➲ बाढ़ नियंत्रण व जल प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का करें अधिक उपयोग

श्री शाह ने जोर देकर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे राज्य और जिला राजमार्गों में भी एक समान डिजाइन परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इससे राजमार्गों की जल निकासी प्रणाली सड़क निर्माण के डिजाइन का अभिन्न अंग बन सकेगी और भारी बारिश की स्थिति में सड़कों पर जलभराव की स्थिति से निपटने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि एनडीएमए को बाढ़ की तैयारियों और रोकथाम के लिए केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्यों के बीच समन्वय के लिए राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए श्री शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को इन शहरों में बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक एवं समयबद्ध कार्रवाई करने और बड़े शहरों में बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाने का आह्वान किया। ■

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

कानपुर में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

औद्योगिक संभावनाओं वाला राज्य बन रहा उत्तर प्रदेश

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को 47,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात
- पनकी एवं घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना और कानपुर मेट्रो के चुन्नीगंज एवं कानपुर सेंट्रल स्टेशन का किया उद्घाटन
- बड़े मेट्रो शहरों में जो बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हैं, वह अब कानपुर में भी दिखने लगे हैं : प्रधानमंत्री

सहकार उदय टीम

उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना केंद्र और राज्य सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन की सरकार आधुनिक और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कानपुर में लगभग 47,600 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया उनमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली विकास परियोजनाओं में शुमार कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस पर करीब 2,120 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा उन्होंने जीटी रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर विस्तार परियोजना और घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की तीन इकाइयों का भी उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-8 और इकोटेक-10 में 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 132 केवी सब-स्टेशनों का भी उद्घाटन उन्होंने किया। इससे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के सेक्टर 28 में 220 केवी सब-स्टेशन की आधारशिला भी इस अवसर पर रखी गई।

प्रधानमंत्री ने कानपुर के पनकी रोड पर पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इससे पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स को कोयला और तेल परिवहन की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए यातायात की भीड़भाड़ भी कम होगी। इस दौरान कानपुर के बिंगवान में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

किया गया। इससे ट्रीटेड सीवेज वाटर का पुनः उपयोग संभव होगा जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और मजबूत बुनियादी ढांचा

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए दो आवश्यक स्तंभ हैं। पहला, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ताकि स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो और दूसरा, मजबूत बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी। पनकी पावर प्लांट (660 मेगावाट), नेवेली पावर प्लांट (660 मेगावाट), जवाहरपुर पावर प्लांट (1320 मेगावाट), ओबरा-सी पावर प्लांट (660 मेगावाट) और खुर्जा पावर प्लांट (660 मेगावाट) की विस्तारित इकाइयों का उद्घाटन करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन बिजली संयंत्रों के चालू होने से राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी जिससे औद्योगिक विकास में और तेजी आएगी। इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्र और राज्य सरकारें आधुनिक और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, श्री मोदी ने कहा कि कभी प्रमुख मेट्रो शहरों तक सीमित रहने वाले बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और संसाधन अब कानपुर में दिखाई देने लगे हैं।

एक्सप्रेसवे का व्यापक नेटवर्क

उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य गड्ढों से भरी सड़कों की अपनी पूर्व पहचान से बहुत आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे के अपने व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जल्द ही कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ की यात्रा के समय को घटाकर केवल 40-45 मिनट कर देगा। इसके अलावा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा, जबकि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे दोनों दिशाओं में यात्रा की दूरी और समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद-अनवरगंज खंड में सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक के कारण कानपुर के निवासियों को लंबे समय से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को 18 रेलवे क्रॉसिंग से जूझना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में एलिवेटेड रेल कॉरिडोर के निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा, गति बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को परिवर्तित कर विश्व स्तरीय सुविधा वाले स्टेशन में अपग्रेड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के मामले में हवाई अड्डे जैसा दिखाई देगा। सरकार अमृत भारत रेलवे स्टेशन पहल के तहत उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास कर रही है जिससे कनेक्टिविटी और यात्री अनुभव में और वृद्धि होगी। स्थानीय उद्योगों और उत्पादन को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन किए गए मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि कानपुर जैसे शहरों को इस पहल से काफी फायदा होगा। कानपुर की औद्योगिक ताकत ऐतिहासिक रूप से इसके एमएसएमई और लघु उद्योगों पर निर्भर रही है। सरकार इन उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है जिससे उनका विकास और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

इस साल के केंद्रीय बजट में एमएसएमई के दायरे को और बढ़ाया गया है और उन्हें अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। एमएसएमई ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही, उनके विकास में सहायता करने के लिए 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कानपुर के पारंपरिक चमड़ा और होजरी उद्योगों को एक जिला, एक उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल कानपुर को लाभ होगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास में भी योगदान मिलेगा। ■

राजस्थान के बीकानेर में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपूर्व गति से काम कर रही सरकार

सहकार उदय टीम

- देश में पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और रेलवे स्टेशनों के विकास में हुई तेज प्रगति
- देश में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का हो रहा आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर हुए तैयार
- सैकड़ों सड़क ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज के निर्माण के साथ ही 34,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे पटरियां बिछाई गईं

देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास में पिछले वर्षों की तुलना में छह गुना अधिक निवेश हो रहा है और इस प्रगति ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय विकास की इन गौरवमयी उपलब्धियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और इन्हें देश को समर्पित करने के अवसर पर देशवासियों से साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों ही आवश्यक हैं। यह सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के हर कोने को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देकर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेल बुनियादी ढांचे और रेलवे स्टेशनों के विकास में तेज प्रगति की है। देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री मोदी ने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए हो रहे निरंतर प्रयासों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशनों का नाम अमृत भारत स्टेशन रखा गया है और ऐसे 100 से अधिक

स्टेशनों का निर्माण पूरा हो चुका है। देश की नई गति और प्रगति के प्रतीक के रूप में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रेलों के शुरुआत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लगभग 70 मार्गों पर वंदे भारत रेल चल रही हैं और इन आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रेल संपर्क स्थापित हो रहा हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन न केवल भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत को संरक्षित करते हैं, बल्कि राज्यों में पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है।

रेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सैकड़ों सड़क ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज के निर्माण के साथ ही 34,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे पटरियां बिछाई गई हैं और ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कार्गो परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित माल गलियारों के तेजी से विकास के साथ ही देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण कार्यों जिक्र करते हुए कहा कि इन प्रयासों के साथ-साथ यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से खुल रहे आर्थिक विकास के नए अवसर

देश भर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने वाले आर्क पुल की कैटेगरी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग और असम में बोगीबील ब्रिज का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने मुंबई में अटल सेतु और दक्षिण भारत में अपनी तरह के अनूठे पंबन ब्रिज का भी जिक्र कर कहा कि बुनियादी ढांचे में

सरकारी निवेश न केवल विकास को गति देता है बल्कि रोजगार के अवसरों का सृजन भी करता है और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इन क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों से सीधे तौर पर श्रमिकों, दुकानदारों, कारखाने के कर्मचारियों और ट्रक एवं टेम्पो ऑपरेटरों जैसे परिवहन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो जाने पर लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं और किसानों को भी अपनी उपज को कम लागत पर बाजारों तक पहुंचाने में सहुलियत मिलती है, जिससे बर्बादी कम होती है। अच्छी तरह से विकसित सड़कें और विस्तारित रेलवे नेटवर्क नए उद्योगों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को काफी बढ़ावा देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च से अंततः हर घर को लाभ होता है, जिसमें युवा लोग उभरते आर्थिक अवसरों से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

गांवों व सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बन रहीं उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें

श्री मोदी ने राजस्थान में जारी बुनियादी ढांचे के विकास से होने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों और यहां तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने जो देकर कहा कि उनके सेवाकाल में अकेले राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार इस वर्ष राज्य में रेलवे विकास पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो कि 11 वर्ष पहले के स्तर की तुलना में 15 गुना वृद्धि को दर्शाता है। बीकानेर को मुंबई से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन को रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। श्री मोदी ने कई क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य, जल और बिजली परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास पर फोकस करते हुए कहा कि इन पहलों का उद्देश्य राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की प्रगति में तेजी लाना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं को अपने शहरों और कस्बों में ही आशाजनक रोजगार के अवसर मिलें।

राजस्थान में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में नई औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ हुआ है। इनके परिणाम स्वरूप राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी और मजबूती मिलेगी, जिससे बीकानेरी भुजिया और बीकानेरी रसगुल्ले को अपने वैश्विक पहचान का विस्तार करने का मौका मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की रिफाइनरी परियोजना अपने अंतिम चरण में है, जिससे राज्य पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। ■

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों की उपलब्धियों पर बोले सहकारिता राज्यमंत्री श्री मोहोल

कमजोर वर्गों को गरिमामय जीवन के साथ मिल रही आर्थिक मजबूती

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अगे बढ़ रहा है। उन्होंने वर्ष 2014 में जब देश की बागडोर संभाली, तब 'विकासशील से विकसित' राष्ट्र बनने की दिशा में एक नया सफर शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष देशसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। सरकार की इन उपलब्धियों को केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा कि इन वर्षों में भारत में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता के खाते में पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को प्रति महीने पांच किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है।किसानों को नियमित आर्थिक सहायता के रूप में सरकार ने अबतक 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पहुंचाया है। देश में किसानों को 25 करोड़ से अधिक 'सॉयल हेल्थ कार्ड' जारी किए गए।

पीएम उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में जरूरतमंद महिलाओं को 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी रसोई गैस की सुविधा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, देशवासियों के लिए हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प के साथ 15.6 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन लगाए गए हैं। गरीब परिवारों के लिए 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण से देशवासियों का जीवन गरिमापूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य योजना' के तहत देश के सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान 52.5 करोड़ मुद्रा लोन छोटे उद्यमियों को मिला।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत गरीबों को पक्का घर देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। श्री मोहोल ने कहा कि ऐसी सैकड़ों योजनाएं धरातल पर उतारी गईं, जिससे आम जनजीवन सरल हुआ। देश में सड़क, रेलवे, हवाई यात्रा और संचार में तेजी आई और डिजिटल सेवाओं के चलते आज देश के पिछड़े गाँव भी 'स्मार्ट विलेज' बनते जा रहे हैं। मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम करते हुए देश के हर वर्ग को जोड़कर 'विविधता में एकता' का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

- श्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ 'विकासशील से विकसित' राष्ट्र बनने की दिशा में एक नया सफर
- पिछले वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ देने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए

भारत के विकास का एक नया द्वार खोला

श्री मोहोल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश अनेक मुश्किलों में जकड़ा हुआ था। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और रोजाना सामने आने वाले नए-नए घोटालों से देश की राजनीति और व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ गया था। ऐसे समय में श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आम जनमानस को आशा की एक नई किरण दी और भारत के विकास का एक नया द्वार खोला। ■

श्री दिलीप संघाणी

सहकारिता के चार वर्षों की नायाब पहलें

सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने में केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद के इन चार वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। श्री शाह के नेतृत्व में जहां सहकारिता की खामियों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल दुरुस्त किया गया वहीं सहकारिता को नई दिशा देने के लिए उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। इसे सहकारिता की दूसरी क्रांति कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस दौरान सहकारिता में 60 से अधिक महत्वपूर्ण पहलें की गई है।

सहकारी संस्थाओं का डेटाबेस तैयार करने में केंद्रीय मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में मंत्रालय का अथक परिश्रम सराहनीय रहा है। मॉडल बायलॉज से पैक्स से अपेक्स तक सुधार दिखा है। देश में सहकारिता को हर गांव तक पहुंचाने के लिए कुल दो लाख अतिरिक्त पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषि, डेयरी और मत्स्य के पैक्स शामिल हैं।

सहकारिता में पारदर्शिता और कार्यदक्षता लाने के लिए पैक्स कंप्युटरीकरण को द्रुत गति से लागू किया गया। सहकारिता के पुनरोद्धार का कार्य श्री शाह ने राज्यों को साथ लेकर पूरा किया। पुराने पड़ चुके सहकारी कानूनों में यथोचित सुधार कर नये प्रावधान लाए गए हैं। सहकारिता में कानूनी सुधार के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में आवश्यक संशोधन किए गए। सहकारिता में चुनाव के लिए अलग से केंद्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

पैक्स को सशक्त करने के लिए उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा गया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को शामिल किया गया है। सहकारिता से युवाओं को जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सहकारिता में प्रशिक्षित कुशल युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसमें इसी सत्र से शिक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय सहकारी प्रशासन, नेतृत्व, उद्यमिता, डिजिटल प्रबंधन, और नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी बैंक, विपणन संघ, आवास समितियों, कृषि सेवा समितियों और अन्य क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

सरकारी चीनी मिलों की समस्याओं का निराकरण करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने उन्हें निजी व सार्वजनिक चीनी मिलों के समान अवसर प्रदान किए हैं। इनकन टैक्स प्रणाली को तर्कसंगत बना दिया गया है। उनकी आर्थिक चुनौतियां दूर कर दी गईं।

राष्ट्रीय स्तर की तीन सहकारी सोसाइटियां बीज, निर्यात और आर्गेनिक्स का गठन किया गया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलने लगी है। देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सहकारिता क्षेत्र ने बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनिया की सबसे बड़ा अन्न भंडारण योजना को हाथ में लिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसकी पायलट परियोजना के पूरा होने के बाद पहले चरण का प्रारंभ कर दिया गया है। किसानों की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उल्लेखनीय पहल की है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का दायित्व दे दिया है। नैफेड और एनसीसीएफ जैसी सहकारी संस्थाएं दलहन व तिलहन की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने लगी हैं

सरकार की पहल पर सहकारी बैंकों को सार्वजनिक व निजी बैंकों जैसी सहूलियत मिलने लगी हैं। उन्हें जहां नई शाखाएं खोलने की सुविधा मिली है वहीं उनकी कारोबारी गतिविधियों को विस्तार मिला है। एनसीडीसी के ऋण वितरण का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसका लक्ष्य पौने दो लाख करोड़ रुपए के पास पहुंचने का अनुमान है। इससे सहकारी संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इन चार वर्षों में 60 से अधिक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे देशभ की सहकारी संस्थाएं लाभान्वित हो रही हैं।

भारत में सहकारी आंदोलन की एक समृद्ध और प्रभावशाली परंपरा रही है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में वर्तमान में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ देशवासियों की सदस्य के रूप में सहभागिता है। ये समितियां कृषि उत्पादन, ग्रामीण वित्त, आवास, मार्केटिंग, उपभोक्ता सेवा, डेयरी सेक्टर, मत्स्य पालन और अन्य उद्योगों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ■

अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) 2025 के एक भाग के रूप में, इफको ने उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्हें सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न नई पहलों की बारीकियों को की जानकारी दी गई। इन प्रयासों से सहकारी शासन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत दशरथ मांझी संस्थान, पटना, बिहार में राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के निदेशक मंडल के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन सहकारी बैंकिंग के भविष्य के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता और एक सहकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी शासन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने एनसीयूआई में देशभर के मत्स्य पालन सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 46 प्रतिनिधियों ने सहकारी मूल्य, नई सहकारी नीति, एमएससीएस अधिनियम और सहकारी शासन के विभिन्न पहलुओं की बारीकियों की जानकारी हासिल की।

इफको ने मलीला, जिला अमरेली में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के अंतर्गत फसल संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, राजकोट के सांसद श्री परषोतमभाई रूपाला, इफको के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार और अमर डेयरी के अध्यक्ष व 2000 से भी ज्यादा किसानों की उपस्थिति में कृषि नवाचार, जल संरक्षण, उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती व योजनाओं के क्रियान्वयन पर संवाद हुआ।

इफको पारादीप इकाई के प्रवेश द्वार पर 'इफको चौक' के उद्घाटन के मौके पर इफको के मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी के साथ पारादीप युनिट के प्रमुख श्री पीके महापात्रा सहित इफको अधिकारी संघ और इफको कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भागीदारी की। यह पारादीप का एक प्रमुख क्रॉस सेक्शन है।

इफको के पारादीप इकाई में अंतर इकाई सांस्कृतिक महोत्सव (आईयूसीएफ) -2025 के भव्य उद्घाटन के बाद इफको की विभिन्न इकाइयों ने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की विविध भारतीय संस्कृतियों को समेटते हुए शानदार प्रदर्शन किए।

बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

Postal Registration No.: DL(S)-18/3560/2023-25

Published on 26-04-2023 Applied for RNI Registration/Exempted for Six Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.21-04-2023